भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1441

07 दिसंबर 2021 को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल में सहकारी ढांचा

1441: डॉ जयंत कुमार राय:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल राज्य में रहकारी ढांचे को मजबूत करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उपर्युक्त राज्य में सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई राशि आंवटित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): देश में पहले से ही एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है । देश में सहकारी क्षेत्र के दो प्रकार के ढांचे हैं - राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां। बहु-राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सहकारी समितियां राज्य सरकार के अधीन आती हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यरत सहकारी समितियां भी शामिल हैं । सरकार अपने दो प्रमुख संस्थानों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से पहले से ही पश्चिम बंगाल राज्य में कई सहकारी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रही है। एनसीडीसी ने कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसी) के तहत पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है:

वर्ष	दी गई सहायता (लाख रुपये में)		
	लोन	सब्सीडी	कुल
2018-19	32302.00	632.13	32934.13
2019-20	11340.00	1243.00	12583.00
2020-21	2229.86	3682.68	5912.54

इसी प्रकार, एनसीसीटी ने कल्याणी में अपने क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के माध्यम से राज्य में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागी	महिला सहभागी
2018-19	80	2046	263
2019-20	100	2346	274
2020-21	54	1199	334

****